

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 79/2018

जोगासिंह पुत्र रणसिंह जाति जटसिख निवासी गांव तामकोट तहसील पदमपुर
जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलांत

बनाम

1. मुरदितसिंह पुत्र रणसिंह जाति जटसिख निवासी गांव तामकोट तहसील पदमपुर
जिला श्रीगंगानगर।

2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार पदमपुर।

अपील अर्न्तगत धारा 225 राज.काश्त. अधिनियम 1955
विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी पदमपुर दिनांक 25.05.2018
उपस्थिति:-

श्री मोहनलाल पूनियां अभिभाषक अपीलार्थी
श्री जीतपालसिंह सेनी, अभिभाषक रेष्यों
श्री महावीर धारणीयां राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 19.06.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेष्यों सं. 1 ने उपखण्ड
अधिकारी पदमपुर के समक्ष दिनांक 21.05.2018 को एक प्रा.पत्र पेश कर निवेदन
किया कि चक 48 आरबी. के मु.नं. 10 के कि.नं. 20, 21 में रास्ता पूर्व से चालू है
जो राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। उक्त प्रा.पत्र पर तहसीलदार से
रिपोर्ट तलब कर पत्रावली दिनांक 25.05.2018 को कायम की एवं उसी दिन प्रा.
पत्र स्वीकार करते हुए मु.नं. 10 के कि.नं. 20, 21 में 2-2 विस्वा रास्ता स्वीकृत
कर दिया जिसके विरुद्ध अपीलांत ने यह अपील पेश की।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांत ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में
वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अपीलांत को
बिना सुने, बिना पक्षकार बनाए पारित किया गया है। अर्थात् न्यायालय द्वारा रेष्यों
के प्रा.पत्र जो बिना किसी कानून के पेश किया गया था, पर तहसीलदार की
रिपोर्ट प्राप्त कर दिनांक 25.08.2018 को पत्रावली कायम कर उसी दिन रास्ता

19/6/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
(रक्ष.)



-2-


स्वीकृत कर दिया। अधी. न्यायालय द्वारा 251ए आर.टी.ए. के प्रावधानों की कोई पालना नहीं की। साथ ही रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में मुआवजा नहीं दिलाया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेषों. ने अपनी बहस में कथन किया कि रेषों. को रास्ता की आवश्यकता थी। अप्रार्थी का सहमति पत्र संलग्न है। रास्ता 1979 से चल रहा है। सहमति से रास्ता स्वीकृत किया गया है जिसमें दूसरे पक्ष को सुनने की आवश्यकता नहीं थी। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अधी. न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/रेषों. द्वारा प्रा.पत्र पेश करने पर तहसील से रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलांट को बिना पक्षकार बनाए एवं बिना सुने आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। अपीलाधीन आदेश राज.कास्त.अधि. की धारा 251ए के तहत पारित किया है जिसकी Bare reading है कि "251-A. Laying of underground pipeline or opening a new way through another khatedar's holding or enlarging the existing way— (1) Where— (a) a tenant intends to lay an underground pipeline through the holding of another khatedar for the purpose of irrigation of his holding; or (b) a tenant or a group of tenants intend to have a new way, or enlargement or widening of an existing way, through the holding of another khatedar to have access to his holding or, as the case may be, their holdings— and the matter is not settled by mutual agreement, the tenant or the tenants, as the case may be, may apply for such facility to the Sub-Divisional Officer concerned, and the Sub-Divisional Officer, if he is satisfied after a summary inquiry, that—

- (i) the necessity is absolute necessity, and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and
- (ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is proved— may, be order, allow the applicant, to lay pipeline, at least three feet beneath the surface of the land, along the line demarcated or pointed out by the tenant who holds that land, or to have a new way, not wider than thirty feet, through the land on such track as pointed out by the tenant who holds that land, and if no such track is pointed out, through the shortest or nearest route, or to enlarge or widen the existing way, not exceeding up to thirty feet, on payment of such compensation as may be determined by the Sub-Divisional Officer, in the prescribed manner, to the tenant who holds the land


19/6/18
रजिस्ट्रार अपील अधिकारी
कैथनगढ़ (राज.)

through which the right to lay pipeline or have a new way, or enlarge or widen an existing way is granted.

(2) Where a right to have a new way or enlarge or widen an existing way is granted under sub-section (1), the tenancy in respect of the land comprising such way shall be deemed to have been extinguished and the land shall be recorded as rasta in the revenue records.

3) The persons permitted to avail any of the facilities referred to in sub-section (1) shall not, by virtue of the said facility, acquire any other right in the holding through which such facility is granted." तथा इस अधिनियम की क्रियान्विति हेतु आज्ञापक प्रावधान किये गये हैं

जिसकी Bare reading है कि 68. Application under section 251-A - An application for grant of permission under sub-section (1) of 251-A of the Act shall be in Form I.

69 Enquiry and disposal of application - On receipt of an application in Form I, the Sub-Divisional Officer shall either inspect the site himself or get it inspected by an-officer not below the rank of the Inspector Land Records and invite objections from the affected persons. The Sub-Divisional Officer after affording an opportunity of being heard to the parties and making such further enquiry, as he thinks necessary, if satisfied that-

(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding and

(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is proved,

may allow the application. The application shall be decided by the Sub-Divisional Officer within 90 days from the date of application.

70. Determination of compensation.- (1) The amount of compensation payable under sub-section (1) of section 251-A of the Act, shall be determined in the following manner:—

(i) if the parties mutually agree on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer shall determine the amount of compensation as per the mutual agreement. (ii) if the parties do not agree mutually on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer shall determine the amount of compensation for the land equivalent to -

(a) two times of the rates recommended by the District Level Committee constituted under clause (b) of sub-rule (1) of rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of a new way or enlargement or widening of an existing way; and

(b) 10% of the rates recommended by the District Level Committee constituted under clause (b) of sub-rule (1) of rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of laying underground pipeline.

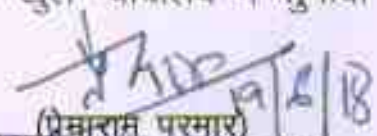


12/6/18
मुख्य अपील प्राधिकारी
बीकानेर (राज.)

(2) In addition to the value of land determined under clause (a) or (b) of sub-rule (1), if any loss or damages caused due to removal of standing trees, crops or structure, the amount of actual loss or damages shall also be determined."

उक्त नियमों में नियम 69 में आज्ञापक प्रावधान किया गया है कि पक्षकारों को सुना जाना आवश्यक है तथा नियम 70 में मुआवजे का प्रावधान दिया गया है जिसकी पालना भी आज्ञापक है परन्तु अधी. न्यायालय द्वारा अपीलाट को किसी भी रूप में नहीं सुना गया तथा अपने निर्णय में मुआवजे का कोई प्रावधान अंकित नहीं किया है। तदानुसार अधी. न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरुद्ध होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलाट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.05.2018 अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।


 (प्रेमराम परमार)
 राज्य न्यायालय अधिकारी
 राजस्व अपील प्राधिकारी
 श्रीगंगानगर

